

भारत के अगले सीजेआई होंगे, जस्टिस सूर्यकांत

सीजेआई गवई ने जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात कर अपना रिकमंडेशन लैटर साँपा

–जाल खंबाता –

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, २७ अक्टूबरा भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो २४ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के ५३वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की।

सरकार ने पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश गवई को एक पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी नाम की सिफारिश करने को कहा था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गवई इस समय भूटान दौरे पर थे। गवई ने अपने वापसी के तुरंत बाद सोमवार (२७ अक्टूबर, २०२५ को (सीफारिश) को सिफारिश पत्र के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत से मुलाकात की, यह दिन दिवाली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला काम दिवस था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें संविधान के अक्टूछेद ३७० का निरस्त करना, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया

रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल टेस्ट किया

माँस्को, २७ अक्टूबरा रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली कूज मिसाइल बुरेवस्तनिक–९एम७३९ का सफल परीक्षण किया है। रूस ने दावा किया है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई

पुतिन ने कहा, इसकी अनलिमिटेड रेंज है, इसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता।

एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है।

रूसी सेना के प्रमुख व्लाैरी गेरैसिमोव ने बताया कि मिसाइल का सफल टेस्ट २१ अक्टूबर को किया गया। इस टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब १५ घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने १४ हजार किलोमीटर की दूरी तय की। गेरैसिमोव ने यह भी बताया कि यह मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, यह इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है।

रूस ने ब्यूरेवस्तनिक को एक नाभिकीय–प्रेरित कूज मिसाइल के रूप में पेश किया है यानी इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर भी रहेगा जो मिसाइल को अनवरत ऊर्जा देगा। जिससे उसकी रेंज सैद्धांतिक तौर पर लगभग अंततः हो सकती है। अगर यह पूरी तरह से सच हुआ तो वाकई रूस दुनिया का पहला देश होगा, जिसके पास इतनी ताकतवर नाभिकीय–प्रेरित मिसाइल होगी।

आखिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक कि जेडीयू नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कथित तौर पर बीमार हैं, भी दर्जनों सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, जैसे कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया है। जेयस्पी नेता प्रशांत किशोर भी लगातार प्रचार दौरें पर हैं। इस बीच, राहुल गांधी को पुरानी दिल्ली की गलियों में ‘इनमार्टिस (हस्तशिल्प) तैयार करते हुए देखा गया है।

कांग्रेस ने २०२४ लोकसभा चुनावों में बिहार की तीन सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से दो सीटें सीमांचल क्षेत्र में हैं, जो पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित हैं, और जहां मतदान दूसरे चरण में ११ नवम्बर को होना है। २०२० विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ७० सीटों पर चुनाव लड़ा था तथा १९ सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर कांग्रेस इन आंकड़ों में सुधार करना चाहती है, तो चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। समय की कमी को देखते हुए, यह देखना होगा कि राहुल गांधी वह ऊर्जा और जादू दोबारा उत्पन्न कर पाते हैं कि नहीं, जो उन्होंने वोट आकर्षण यात्रा के दौरान पैदा किया था।

- जस्टिस गवई जो २४ नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं, से केन्द्र सरकार ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने को कहा था।**

- मूलतः हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे धारा ३७० हटाना, इलैक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराना, स्पायवेयर पैगसस केस और राजद्रोह कानून को रद्द करना आदि।**

था, शामिल हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया था। वह पेगासस स्पाइवेयर मामले और देशद्रोह कानून के लिलंबन वाली बेंच का भी हिस्सा थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म १० फरवरी १९६२ को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने गृह नगर से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने १९८४ में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत हिसार जिला अदालत से की और १९८५ में पंजाब और हरियाणा उच्च

न्यायालय में वकालत शुरू करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।

वह ७ जुलाई, २००० को हरियाणा के सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता बने और मार्च २००१ में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। ९ जनवरी, २००४ को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। अक्टूबर २०१८ में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

उन्हें २४ मई, २०१९ को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल ९ फरवरी, २०२७ तक रहेगा।

नयी दिल्ली, २७ अक्टूबरा भारत–आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर गए विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और कई अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। डा. जयशंकर ने इन नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की। रूबियो से मिलने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा, “आज सुबह कुआलालंपुर में मार्क रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ–साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की।” विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ा देने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद–प्रशांत क्षेत्र को विकसित करने के बारे में बात की।

अमेरिका के विदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माँस्को के साथ अपने संबंधों को लेकर नई दिल्ली पर दबाव बनाने में कोई संकोच नहीं किया है। रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से भारत का इनकार वांशिगटन को लगातार परेशान कर रहा है। इसलिए, रूबियो की यह नरम पहल यह स्वीकारोक्ति थी है कि दबाव की एक सीमा होती है, और अनुनय–विनय तब ज्यादा कारण होती, जब भारत को अमेरिकी रणनीतिक दायरे में बनाए रखना लक्ष्य हो।

नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, इस बैठक ने दोहरा उद्देश्य भी पूरा किया। इसने वांशिगटन को याद दिलाया कि भारत के साथ साझेदारी स्वतः नहीं होती, इसे भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता के सम्मान के माध्यम से

सितम्बर में १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं

ने किया मोबाइल नंबर बदलने का आवेदन

नयी दिल्ली, २७ अक्टूबरा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए सितंबर महीने में १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं ने आवेदन किया।

संचार मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि कुल १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं में से जेोन–१ (उत्तर एवं पश्चिम भारत) के ८४.५ लाख और जेोन–२ (दक्षिण एवं पूर्वी भारत) के ६६.८ लाख उपभोक्ता शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्किल से सबसे अधिक २०.८ लाख उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए आवेदन किया। दूसरे स्थान पर १४.५ लाख के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्किल का स्थान रहा। सितंबर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अगस्त की तुलना में ०.६१ प्रतिशत बढ़ कर ९९.५६ लाख पर पहुंच गयी। इसमें ९३.८९ लाख मोबाइल ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर थे। सबसे अधिक ५०.५५ लाख ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर रिलायंस जियो के थे। भारती एयरटेल ३१.०४ लाख के साथ दूसरे और वोडाफोन आइडिया १२.७८ लाख के रूप थ तीसरे स्थान पर रहा। मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में रिलायंस जियो के मोबाइल सबस्क्राइबर ०.६८ प्रतिशत, बीएसएनएल के ०.५७ प्रतिशत और भारती एयरटेल के ०.११ प्रतिशत बढ़े। वोडाफोन आइडिया के सबस्क्राइबरों की संख्या ०.३७ प्रतिशत घट गयी।

उन्हें २४ मई, २०१९ को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल ९ फरवरी, २०२७ तक रहेगा।

आसियान सम्मेलन में रूबियो के अलावा कई नेताओं से भी मिले जयशंकर

- इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल थे**

उन्होंने मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा के साथ–साथ म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

डा. जयशंकर आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी मिले। उन्होंने जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। दोनों के बीच सहयोग के अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के बारे में मिलकर काम करने पर सहमति हुई। उन्होंने वैश्विक स्थिति और हिंद–प्रशांत सहयोग पर भी

सितम्बर में १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं

ने किया मोबाइल नंबर बदलने का आवेदन

नयी दिल्ली, २७ अक्टूबरा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए सितंबर महीने में १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। संचार मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि कुल १.५१ करोड़ उपभोक्ताओं में से जेोन–१ (उत्तर एवं पश्चिम भारत) के ८४.५ लाख और जेोन–२ (दक्षिण एवं पूर्वी भारत) के ६६.८ लाख उपभोक्ता शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्किल से सबसे अधिक २०.८ लाख उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए आवेदन किया। दूसरे स्थान पर १४.५ लाख के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्किल का स्थान रहा। सितंबर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अगस्त की तुलना में ०.६१ प्रतिशत बढ़ कर ९९.५६ लाख पर पहुंच गयी। इसमें ९३.८९ लाख मोबाइल ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर थे। सबसे अधिक ५०.५५ लाख ब्रॉडबैंड सबस्क्राइबर रिलायंस जियो के थे। भारती एयरटेल ३१.०४ लाख के साथ दूसरे और वोडाफोन आइडिया १२.७८ लाख के रूप थ तीसरे स्थान पर रहा। मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में रिलायंस जियो के मोबाइल सबस्क्राइबर ०.६८ प्रतिशत, बीएसएनएल के ०.५७ प्रतिशत और भारती एयरटेल के ०.११ प्रतिशत बढ़े। वोडाफोन आइडिया के सबस्क्राइबरों की संख्या ०.३७ प्रतिशत घट गयी।

आसियान सम्मेलन में रूबियो के अलावा कई नेताओं से भी मिले जयशंकर

- इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल थे**

उन्होंने मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा के साथ–साथ म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

डा. जयशंकर आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी मिले। उन्होंने जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। दोनों के बीच सहयोग के अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के बारे में मिलकर काम करने पर सहमति हुई। उन्होंने वैश्विक स्थिति और हिंद–प्रशांत सहयोग पर भी

स्वदेशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जो मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचपीडीआर) प्लेटफ़ॉर्म के रूप में और आपात स्थिति में अस्पताल जहाज के रूप में कार्य करने में सक्षम है। इश्क महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाये गये आवास की सुविधा वाला पहला एसवीएल जहाज भी है जो भविष्य के लिए तैयार बड़े के प्रति भारतीय नौसेना के समवायों और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

पुणे, २७ अक्टूबरा महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को पुणे में कई जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में एटीएस ने २८ वर्षीय पुर्ब हंगरीकर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई कोंड वा इलाके में की गई। यह कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। हंगरीकर को ४ नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एटीएस ने ९ अक्टूबर को पुणे में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस तलाशी अभियान में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और साहित्य जब्त किए गए थे। जांच के दौरान सामने आई आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर, २००८ में

दूसरे चरण की एसआईआर कवायद आज से शुरू

१२ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की नई मतदाता सूचियां बनेंगी

नयी दिल्ली, २७ अक्टूबरा चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत १२ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विषेश गहन पनरीक्षण अर्थात स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन (एसआईआर) का काम मंगलवार से शुरू करने की घोषणा की है जो सात फरवरी तक संपन्न कर लिया जायेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यहां एक विशेष संवादादाता सम्मेलन में एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि इस संवैधानिक कार्य में आयोग को सभी राज्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर कराया जाना है, उनमें अंडमान–निकोबार, चंडीगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों की मतदाता सूचियों में आज आधी रात के बाद तब तक कोई बदलाव नहीं किया जायेगा जब तक कि एसआईआर का काम संपन्न नहीं हो जाता। इसके साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों–कर्मचारियों के

चरण में एसआईआर कराया जाना है, उनमें अंडमान–निकोबार, चंडीगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों की मतदाता सूचियों में आज आधी रात के बाद तब तक कोई बदलाव नहीं किया जायेगा जब तक कि एसआईआर का काम संपन्न नहीं हो जाता। इसके साथ ही इस कार्य से जुड़े अधिकारियों–कर्मचारियों के

राम मंदिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी देश–दुनिया के भक्तों से सोशल मीडिया के जरिये साझा की। उन्होंने बताया कि १६१ फीट ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर का दूसरा तल पूरी तरह से बनकर तैयार है।

अब केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगले एक पखवाड़े के भीतर यह काम भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि संपत् मंडप के सात मंदिरों (महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शंभरी, ऋषि पत्नी अहिल्या) का निर्माण भी पूरा हो गया है। संत तुलसीदास का मंदिर भी पूरा हो गया है। गिद्ध राज जटायु और गिलहरी की मूर्ति भी परिसर में स्थापित हो गई है। ट्रस्ट महासचिव के अनुसार, दर्शनार्थियों की सुविधा और व्यवस्था से सीधे जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

बताया कि, ध्वजराहीरुह समारोह के बाद परिसर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन मिलने लगेंगे।

पुणे में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी

- तलाशी के दौरान एटीएस को आपत्तिजनक साहित्य, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण एवं दस्तावेज मिले।**

संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, १९६७ के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, एटीएस ने जुबेर हंगरीकर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे की जाँच महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की जा रही है।

इससे पहले, पुलिस ने दिल्ली में

- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रैस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी और कहा अगर किसी मतदाता को दो जगह नाम होने पर दो फॉर्म मिल जाते हैं तो बेहतर होगा वह एक ही फॉर्म जमा करवाएं, वरना उसके कृप्य का अपराध माना जाएगा।**

- दूसरे चरण में राजस्थान में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, प.बंगाल, तमिलनाडु, गोवा के साथ ४ केन्द्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी।**

तबादले आयोग की अनुमति से ही किये जा सकेंगे।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर के दूसरे चरण में तीन नवंबर तक फार्मों की छपाई और कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा, चार नवंबर से चार दिसंबर तक बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), प्रशासन के वॉलंटियर और राजनीतिक दलों के एजेंटों के माध्यम से घर–घर जाकर छपे हुए निर्वाचक गणना फार्मों का वितरण और उन्हें वापस एकत्रकर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास जमा करवाने की प्रक्रिया चलेगी।

कार्यक्रम के अनुसार गणना फार्मों की प्राप्ति के आधार पर संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की नयी मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को प्रकाशित कर दिया जायेगा और उसी दिन से आठ जनवरी २०२६ तक उन पर दावे और

आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। नौ से ३१ जनवरी तक नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी और पक्की मतदाता सूची सात फरवरी को जारी कर दी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के पहले चरण में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए बिहार की साढ़े सात करोड़ मतदाताओं की पूर्ण भागीदारी को लेकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार की पक्की सूची पर दावे और आपत्तियां शून्य के बराबर हैं, जो दर्शाती हैं कि राज्य की मतदाता सूची अधिकतम रूप से शुद्ध है। उन्होंने इन राज्यों के मतदाताओं को कानून के अनुसार केवल एक ही मतदाता गणना फॉर्म जमा कराने की सलाह दी।

मुख् चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की ही तरह एसआईआर के दूसरे

स्ट्रीट डॉग्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल व तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया

नई दिल्ली, २७ अक्टूबरा आगरा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा, बाकी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ३ नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।(२१ अगस्त को, कोर्ट ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का

- इन सभी राज्यों को स्ट्रीट डॉग्स पर २२ अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट देनी थी।**

निर्देश दिया था। आज, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस सदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नोट किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किया है।

मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित रूप से को नोटिस जारी किया था और आदेश की बड़े पैमाने पर रीपॉर्टिंग भी हुई थी। जस्टिस नाथ ने कहा, "लगातार घटनाएं"

सीजेआई गवई पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलया बागची की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना और सोशल मीडिया पर महिमामंडन रोकने के लिए आदेश की मांग की गयी। एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि शुरुआत में मामला समाप्त हो गया था,

‘एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए’

श्रीनगर, २७ अक्टूबरा। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ।

अब्दुल्ला ने विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर के कार्यान्वयन को लेकर पहले ही कुछ शिकायतें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, "हमें यह भी नहीं पता कि एसआईआर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं जिन्हें यह मिलेगा। पहले बिहार में चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि एसआईआर वाकई फायदेमंद है या नहीं।"मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह इस प्रणाली को कहीं और लागू करने से पहले नतीजों का इंतजार करे। उन्होंने कहा, "बिहार के नतीजे अभी नहीं आए हैं।" चुनाव आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब ऐसा

चरण में भी २००२ से लेकर २००४ के बीच में करायी गयी पिछली एसआईआर के बाद तैयार सूचियों को मिलान का आधार बनाया जायेगा। इन राज्यों और क्षेत्रों की वर्तमान सूचियों के मिलान का कार्य इनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने कर लिया है।

बिहार में एसआईआर के राजनीतिक विरोध के बारे में एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वह ऐसा नहीं मानते कि वहां राजनीतिक दलों का विरोध था। राज्यों में १२ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के १.०६ लाख बूथ स्तरीय एजेंटों ने बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बढ़ –चढ़ कर सहयोग किया। सभी जिला अध्यक्षों ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग दिया और चुनाव से पहले आयोग के दौरे में इन दलों ने नेताओं ने एसआईआर की सराहना की।

‘ अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव प्रचार के लिए उतारा है, इस उम्मीद में कि उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन मोदी की सत्ता के चरम पर भाजपा अपने किसी खास को मुख्ममंत्री नहीं बना पाई है।

लेकिन पार्टी उम्मीद में जी रही है !!!

स्ट्रीट डॉग्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल व तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया

नई दिल्ली, २७ अक्टूबरा आगरा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा, बाकी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ३ नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।(२१ अगस्त को, कोर्ट ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का

सीजेआई गवई पर ...

जब सीजेआई ने किशोर को माफ कर दिया था, लेकिन राकेश किशोर ने मीडिया से कहा कि भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया और इस पर सोशल मीडिया पर भीमस बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका का मजाक बन रहा है।

विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपने कृत्य को दोहराने की कसम भी खाई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि राकेश किशोर का व्यवहार गंभीर आपराधिक अवमानना जैसा है, लेकिन जब सीजेआई ने माफ कर दिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को अवमानना के मामलों में अवमानना कार्रवाई का निर्णय संबंधित जज पर निर्भर होता है।

‘एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए’

- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि बिहार के नतीजे आने के बाद ही एसआईआर दूसरा चरण शुरू करना चाहिए।**

लोगा कि आयोग अपनी स्वतंत्रता खो रहा है और किसी राजनीतिक दल के दबाव